संसद के समक्ष अभिभाषण – 18 फरवरी 1983

लोक सभा	-	सातवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	ज्ञानी जैल सिंह
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री एम. हिदायतुल्लाह
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. बलराम जाखड़

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 1983 में, संसद के इस पहले अधिवेशन में, मैं आपका स्वागत करता हूं। आने वाला वर्ष हमारे लिए चुनौतियों और अवसरों से भरा हुआ है, जिसके लिए संसद, सरकार और जनता को मिल-जुल कर काम करना होगा।

आर्थिक मोर्चे पर, आवश्यकता इस बात की है कि अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जाए, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जाए, अनुत्पादक खर्च को खत्म किया जाए और कीमतों पर काबू रखा जाए। कई देशों में मुद्रा फैलाव के बावजूद, हम मुद्रा के फैलाव पर नियंत्रण रखने में सफल रहे हैं, जिस पर हमारा गर्व करना वाजिब है। वर्ष 1983 की मध्य जनवरी में थोक बाजार कीमतें इससे पहले के 12 महीनों की अपेक्षा केवल 2.8 प्रतिशत ही अधिक रहीं और यह सब उस व्यापक सूखे के बावजूद है, जिसकी लपेट में 4.8 करोड़ हेक्टेयर भूमि आ गई थी और 31.2 करोड़ लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया और उसे अधिक कुशल बनाया गया। पिछले तीन वर्षों में लगभग 50,000 उचित दर की दुकानें खोली गईं। इस वर्ष केन्द्रीय सरकार सूखा, बाढ़ और तूफान के शिकार लोगों को राहत देने के लिए राज्यों को लगभग 700 करोड़ रुपये की राशि देगी, जो राहत कार्य के लिए किसी भी वर्ष में दी जाने वाली राशि से ज्यादा है। इन कुदरती आफतों के शिकार लोगों से हमें हमदर्दी है और हम उनके साहस और राहत कार्यों में लगे कार्यकर्ताओं की कर्त्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हैं।

हमारे बुनियादी ढांचे और हमारे उद्योग ने विकास की गति को बनाए रखा है। अप्रैल, 1982 और दिसम्बर, 1982 के बीच, बिजली के उत्पादन में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कोयले का उत्पादन 4.2 प्रतिशत बढ़ा तथा सीमेंट का उत्पादन 10.2 प्रतिशत और फर्टिलाइजर का उत्पादन 9.6 प्रतिशत बढ़ा है। रेलगाड़ियों द्वारा माल की ढुलाई 3.5 प्रतिशत बढ़ी है। बन्दरगाहों में, जहाजों को माल उतारने के लिए जो काफी समय तक इन्तजार करना पड़ता था, वह अब लगभग खत्म हो गया है। इस्पात के उत्पादन में फिर से बढ़ोतरी हुई है। तेल की ऊंची कीमतें अर्थव्यवस्था पर बोझ बनी रहीं, परन्तु इस अरसे के दौरान देश में कच्चे तेल का उत्पादन 30.6 प्रतिशत बढ़ा है। जहां 1980-81 में, कच्चे तेल का उत्पादन 1.05 करोड़ मीट्रिक टन था, वहां 1981-82 में यह उत्पादन 1.62 करोड़ मीट्रिक टन हो गया और अनुमान है कि 1982-83 में यह उत्पादन बढ़कर 2.1 करोड़ मीट्रिक टन हो जाएगा। भुगतान शेष की कठिनाइयों, मौसम की प्रतिकूल स्थितियों और साधनों की भारी कमी के बावजूद, अर्थव्यवस्था में लगातार दूसरे वर्ष भी उचित विकास हुआ है। चालू वर्ष के पहले 9 महीनों में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल टर्न ओवर 21 प्रतिशत बढ़ा है। लघु उद्योग क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है और इसने लगभग 10 प्रतिशत के विकास की दर को बनाए रखा है। खरीफ और रबी की फसलों के सामने आई समस्याओं के बावजूद, चावल और गेहूं की वसूली इससे पहले के किसी भी वर्ष की अपेक्षा अधिक रही। सरकार ने किसानों को वसूली की ऊंची कीमतें दी हैं।

निर्यात में वृद्धि को कायम रखा जा रहा है। पिछले वर्ष के पहले सात महीनों की अवधि में, निर्यात के अनन्तिम आंकड़े 3,960 करोड़ रुपये थे, जब कि चालू वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान निर्यात उससे लगभग 17.8 प्रतिशत अधिक होने की आशा है। आयात में तीव्र वृद्धि की प्रवृत्ति को रोक दिया गया है। हालांकि हमारी अर्थव्यवस्था की विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए कुल आयात खर्च में कुछ वृद्धि दिखाई पड़ सकती है, फिर भी, तेल की खोज में तेजी से काम करने के कार्यक्रम और इस्पात तथा फर्टिलाइजर्स जैसे अन्य क्षेत्रों में अधिक उत्पादन और पूंजी लगाए जाने से, आयात में और आगे वृद्धि पर काबू रखना सम्भव हो सकेगा। विकासशील देश जिस कच्चे माल का निर्यात करते हैं, उसकी कीमतों में तेजी से गिरावट आई है, परन्तु जिस तैयार माल को हम आयात करते हैं उनकी कीमतें काफी बढ़ गई हैं। पश्चिमी देशों में ब्याज की ऊंची दरों ने भारत जैसे देशों के लिए स्थिति को और भी गम्भीर बना दिया है।

संसार एक गम्भीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। बहुत से देश मंदी की लपेट में हैं और वे इन्वेस्टमेंट में कटौती करते रहे हैं। फिर भी हमने अपनी विकास की गति को बनाए रखा है। केन्द्रीय योजना खर्च 27 प्रतिशत बढ़ गया है और केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं को मिलाकर उन पर कुल खर्च 21 प्रतिशत बढ़ गया है।

14 जनवरी, 1982 को घोषित संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम के, जिसमें निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगों की भलाई पर बल दिया गया है, उत्साहजनक नतीजे निकले हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन इस वर्ष 33 करोड़ से अधिक अतिरिक्त श्रम दिवसों का देहाती रोजगार पैदा किया जाएगा। खादी और ग्राम उद्योग कमीशन के कार्यकलापों में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और सक्रिय रूप से इस बात के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि इनका संबंध ग्रामीण रोजगार के लिए की जा रही सभी कोशिशों के साथ जोड़ दिया जाए। पीने के पानी की सुविधा ऐसे और 24,000 गांवों में पहुंचाई गई जहां पीने के पानी की समस्या थी। 5 लाख 40 हजार मकान बनाने के लिए जगह दी गई है। आवास और शहरी विकास निगम 2 लाख 35 हजार घर बनाने के लिए सहायता देगा। इस वर्ष 23.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा जुटाई जा रही है।

जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई है, राष्ट्र उनका कृतज्ञ है। उनके प्रति आभार के प्रतीक के रूप में सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना में विस्तार किया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह प्रयत्नशील है और इसके लिए उसने त्रिमुखी नीति तैयार की है। इसमें राज्यों की विशेष कम्पोनेन्ट योजनाओं, और अनुसूचित जाति विकास निगमों के अलावा राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों की विशेष कम्पोनेन्ट योजनाएं, और विशेष केन्द्रीय सहायता भी शामिल हैं। जनजातीय उप-योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता को वर्ष 1982-83 में 85 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 95 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

हमारे समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और पिछड़ी श्रेणियों के लोगों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति की दिशा में किए जा रहे कार्य को सरकार के विकास कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी जाती रहेगी। केन्द्र द्वारा प्रायोजित मछुआरों की एक बीमा योजना भी शुरू की गई है।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों में लोगों के भाग लेने और उसके आम समर्थन की एक लहर पैदा हुई। अप्रैल, 1982 से जनवरी, 1983 की अवधि के दौरान परिवार नियोजन के सभी तरीकों को स्वीकार करने वालों की संख्या इससे पहले वर्ष की इसी अवधि की संख्या से 16% अधिक थी। संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन कुष्ठ रोग, नेत्रहीनता और तपेदिक पर नियंत्रण पाने के कार्यक्रमों को एक नये जोश के साथ लागू किया जा रहा है।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिए हमें उतनी ही चिन्ता है जितनी कि कृषि मजदूरों और किसानों के लिए है। औद्योगिक विवाद एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं उनमें शिकायतों को निपटाने के लिए एक अंदरूनी मशीनरी की व्यवस्था है और उनमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि श्रम न्यायालय एक निर्धारित समय में ही अपना निर्णय दे दें।

शिक्षा के स्तर में सुधार लाने, बालिगों में निरक्षरता समाप्त करने और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने के कार्यक्रमों और नीतियों को जिसमें बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, उच्च प्राथमिकता दी जाती रही है।

पिछले वर्ष की दो महत्वपूर्ण घटनाएं रहीं, जिनका हमारे नौजवानों के भविष्य पर और उनकी शारीरिक तथा मानसिक स्फूर्ति पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। ये घटनाएं हैं– खेल विभाग की स्थापना और सफलता के साथ एशियाई खेलों का आयोजन। जिस ढंग से इन खेलों का आयोजन किया गया, उसकी व्यापक सराहना हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुताबिक खेलकूद सुविधाओं के जुटाए जाने और 17 स्टेडियमों के निर्माण एवं दर्जा बढ़ाये जाने ने यह सिद्ध कर दिया है कि हम बड़े पैमाने पर खेलों को आयोजित करने की क्षमता रखते हैं। खेलकूद का यह बुनियादी ढांचा आने वाले वर्षों में हमारे पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों के काम आता रहेगा।

एशियाई खेलों के कारण हमें बहुत से नए क्षेत्रों में दूरदर्शन का विस्तार करने और रंगीन प्रसारण का "प्रारम्भ" करने का अवसर भी मिला है। हमारी दूरदर्शन नीति में देहाती लोगों की जरूरतों, और शिक्षा तथा विकास के लिए इस शक्तिशाली माध्यम के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हमारे लिए यह घटनापूर्ण वर्ष रहा है। हमने टेक्नोलॉजी संबंधी अपना नीति वक्तव्य तैयार किया है और उसकी घोषणा कर दी है, जिसमें उन बातों को निर्धारित किया गया है जो देसी टेक्नोलॉजी के विकास और ऐसी टेक्नोलॉजी के आयात के संबंध में निर्णय लेने में हमारा मार्गदर्शन करेगी, जिससे हम शक्तिशाली हों। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में अपना कार्य जारी रखेंगे। हम मूल विज्ञान के साथ-साथ बायो टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, न्यूक्लियर साइंस में फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी और समुद्र इंजीनियरी जैसे नए क्षेत्रों की ओर ध्यान दे रहे हैं। दक्षिणी ध्रुव में अब हमारा दूसरा वैज्ञानिक अभियान चल रहा है जिसमें महत्वपूर्ण प्रयोग किए जा रहे हैं और भविष्य में एक ऐसा स्थायी केन्द्र कायम करने के लिए स्थान का सर्वे किया जा रहा है जहां आदमी रह कर काम कर सके। सागर तल में पोली-मेटलिक नोड्यूल्स के सर्वे के हमारे कार्य को सागर नियम सम्मेलन में पायोनीर इन्वेस्टर के रूप में मान्यता मिली है। भारत ही एकमात्र ऐसा विकासशील देश है जिसे इस प्रकार की मान्यता हासिल हुई है।

इस वर्ष इनसेट-1बी छोड़ा जाएगा जो ऊंचे दर्जे की दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विज्ञान संबंधी क्षमता हासिल करने में हमारी सहायता करेगा। इनसेट-1ए के छोड़े जाने से पहले जिसका मूल डिजाइन ठीक था जो अनुभव हमें हासिल हुआ उसे ध्यान में रखते हुए इनसेट-1बी में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

माननीय सदस्यगण, उन समस्याओं से वाकिफ हैं, जो तारापुर न्यूक्लियर पावर रियेक्टर के लिए ईंधन की पूर्ति को निश्चित रूप से बरकरार रखने में हमारे सामने आई हैं। इन्हें अब फ्रांस और अमरीका की सरकारों के साथ सलाह-मशवरे से हल कर लिया गया है।

अब मैं देश की अंदरूनी राजनीतिक स्थिति की ओर आता हूं। फूट डालने वाली और विघटनकारी ताकतें हिंसा भड़काने और राष्ट्रीय ढांचे को कमजोर करने में लगी हुई हैं। इनका मुकाबला दृढ़ता के साथ किया जाना चाहिए। असम और पंजाब जैसे मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श में विरोधी दलों को शामिल करने के लिए सरकार ने पहल की है और यह सराहनीय प्रवृत्ति जारी रहनी चाहिए। बहुत से क्षेत्रों में साम्प्रदायिक और राष्ट्रविरोधी तत्व आपत्तिजनक गतिविधियों में लगे हुए हैं। इनको कारगर ढंग से दबाना होगा। उत्तर-पूर्वी कुछ राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में उग्रवादी संगठन सरगर्म हैं। इनकी गतिविधियों से निपटने तथा शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए हमने अच्छे तालमेल के साथ एक अभियान चलाया है। इसी बीच पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विकास कार्यों की गति को बढ़ाया गया है।

हाल में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा और संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली में और इससे पहले हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं। मेघालय में चुनाव अभी-अभी समाप्त हुए हैं और असम में चुनाव चल रहे हैं। ये चुनाव हमारी लोकतांत्रिक परम्परा का हिस्सा और एक संवैधानिक जिम्मेदारी रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बिगड़ गई है। तटवर्ती देशों की इच्छाओं का अनादर करते हुए हिन्द महासागर में विदेशी सैनिकों का बढ़ता हुआ अनधिकार प्रवेश, ईरान और इराक के बीच लगातार युद्ध, इज़राइल का बढ़ता हुआ दु:साहस और फिलिस्तिनियों की मुसीबतें, दक्षिण अफ्रीका की जातिवादी सरकार की अपनी ही जनता और अपने पड़ोसी देशों के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाइयां तथा नि:शस्त्रीकरण की बातचीत, और उत्तर-दक्षिण वार्ता में गतिरोध—ये सब चिंताजनक मामले हैं। दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व एशिया के हालात के राजनीतिक हल अभी निकाले जाने बाकी हैं।

पड़ोसी देशों में होने वाली कुछ-एक गतिविधियों से हमारी सुरक्षा का वातावरण बिगड़ा है। हमारे पड़ोसी देश, पाकिस्तान द्वारा सोफिस्टिकेटेड हथियार हासिल किए जाने से सारा राष्ट्र चिन्तित है। हमारी अपनी नीति पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने और इस दिशा में पहल करने की रही है। उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ और दोनों देशों के अधिकारियों के बीच जो बैठकें हुई हैं, उनसे अंतत: शांति, दोस्ती और सहयोग के स्थायी संबंधों का रास्ता तैयार होगा।

बांग्लादेश के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक के साथ भी हमारी बातचीत हुई है। इनसे हमारे दोस्ती के संबंध और मजबूत हुए हैं। चीन के साथ सीमा के सवाल तथा दोनों

देशों के अन्य आपसी मामलों पर सरकारी-स्तर की बातचीत का तीसरा दौर पिछले महीने बीजिंग में हुआ था। भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ हमारे अच्छे संबंध बने रहे हैं।

सारे संसार में तथा अपने क्षेत्र में शांति, दोस्ती और स्थिरता बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्षता की हमारी नीति ने हमें बिना विचलित हुए काम करने में सहायता दी है। जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं, अगले महीने के शुरू में दिल्ली में गुटनिरपेक्ष देशों का सातवां सम्मेलन हो रहा है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा सर्वसम्मति से अनुरोध किए जाने पर हम इस सम्मेलन की मेज़बानी कर रहे हैं। हमारे देश में होने वाला राष्ट्राध्यक्षों का यह सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। हम यह आशा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने जो समस्याएं हैं उनके हल निकालने में यह शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण योगदान देगा। बाद में इसी वर्ष राजधानी में एक और मुख्य सम्मेलन हो रहा है, वह है राष्ट्रमण्डल देशों की सरकारों के अध्यक्षों की बैठक। इन दोनों सम्मेलनों को सफल बनाने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए।

मैं अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति द्वारा की गई आयरलैण्ड तथा यूगोस्लाविया और हमारी प्रधानमंत्री की ब्रिटेन, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, मारीशस, मुज़ाम्बिक और सोवियत संघ की यात्राओं का भी जिक्र करना चाहूंगा तथा साथ ही तंज़ानिया और ग्रीस के राष्ट्रपतियों, भूटान नरेश, मुज़ाम्बिक, अल्जीरिया, नौरू, पाकिस्तान, फ्रांस, मिस्र और नाईज़ीरिया के राष्ट्रपतियों, ब्रिटेन, नेपाल और मारीशस के प्रधानमंत्रियों, फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे के अध्यक्ष, बांग्लादेश के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक तथा दूसरे राजनेताओं द्वारा की गई भारत की यात्राओं का भी उल्लेख करूंगा। यात्राओं के इस आदान-प्रदान से आपसी लाभ हुआ है।

माननीय सदस्यगण, संसार में आर्थिक और राजनैतिक संकटों के कारण जो तनाव बढ़ा है उसका मुकाबला भारत केवल चौकसी, एकता और अपनी उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग द्वारा ही कर सकता है। भ्रष्टाचार और अकुशलता से जूझने के अलावा, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मतभेदों को इस तरह प्रकट न किया जाए जिससे हिंसा भड़के या हमारी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो। पिछले तीन वर्षों में हम अपनी स्थिरता और प्रगति को बरकरार रख सके हैं। मेरा हार्दिक अनुरोध है कि समस्त राष्ट्र भारत की अखण्डता को बनाए रखने और उसके कल्याण तथा सम्मान को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करें।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि उनके सामने जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें सहयोग और सद्भावना से पूरा करें। बजट कार्य, विधायी कार्य तथा अन्य कार्य जो आपके सामने हैं उन्हें सफलता के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं पेश करता हूं।

जय हिन्द।